लोकतंत्र की आत्मा है - संवाद

हरियाणा संवाद

पाक्षिक 1-15 दिसंबर 2021 www.haryanasamvad.gov.in अंक -31

"दुनिया को आप अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए, आपके पास भी सर्वश्रेष्ठ ही लौट कर आएगा।"
: स्वामी दयानंद सरस्वती

सुई गांव का विकास देखने पहुंचे राष्ट्रपति

3

गोवंश अनुसंधान केंद्र पिंजौर

5

अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में हरियाणा की धूम

8

अभूतपूर्व

डिजिटलाइज़ हुआ राजस्व रिकॉर्ड

विशेष प्रतिनिधि

प्रदेश के राजस्व रिकॉर्ड को डिजिटलाइज़ किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'डिज़िटल इंडिया मिशन' के तहत हरियाणा सरकार का यह उल्लेखनीय एवं ऐतिहासिक कदम है। राज्य स्तर व जिला स्तर के 18.50 करोड़ रुपए के राजस्व रिकार्ड को स्कैन कर डिज़िटल किया गया है। यह पूरा लेखा जोखा कम्प्यूटर के माउस की एक क्लिक पर आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। कामकाज में पारदर्शिता के साथ भ्रष्टाचार की गुंजाइश को समाप्त करने की ओर यह एक महत्त्वपूर्ण कदम साबित होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में सभी 22 जिलों में बने आधुनिक अभिलेख कक्ष (माडर्न रेवन्यू रिकार्ड रूम) का लोकार्पण किया है।

गठरियों में बंधे पुराने राजस्व रिकार्ड को संभालना, संरक्षित रखना व उसे बार-बार ढूंढना मुश्किल कार्य था। इसे ढूंढने में समय भी अधिक लगता था और रिकॉर्ड खराब होने, कटने-फटने, गुम होने व रिकार्ड से छेड़छाड का अंदेशा भी बना रहता था। प्रदेश में पहला माडर्न रेवन्यू रिकॉर्ड रूम जिला कैथल में 24 जून 2017 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तैयार किया गया था तथा इसके बाद 25 दिसंबर 2019 को 'सुशासन दिवस' के अवसर पर सभी जिलों के लिए माडर्न रेवन्यू रिकॉर्ड रूम परियोजना की शुरुआत की गई थी। यह रिकॉर्ड रूम सभी जिलों में तय समय से पहले बनाकर तैयार किए गए हैं। पूरे देश में आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और हरियाणा में महत्वपूर्ण रेवन्यू रिकॉर्ड को डिजिटलाइज़ कर ई-गवर्नेंस सेवाओं में और विस्तार किया गया है। भविष्य में अन्य विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण रिकॉर्ड को भी इसी तरह डिजिटलाइज़ किया जाएगा। इस रिकार्ड के डिजिटलाइज़ होने से अनेक योजनाओं के क्रियान्वयन में भी तेज़ी आएगी और जनता को काफ़ी सहूलियत मिलेगी।

राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने जमाबंदी, म्यूटेशन, मिसल हकीयत, रजिस्टर्ड डीड, फील्ड बुक्स, मुसावीयस, रिवेन्यू कोर्ट केस मामलों के निर्णय, ज़मीनों के नक्शे आदि के रिकॉर्ड को आधुनिक राजस्व रिकॉर्ड रूम में स्कैनिंग और डिजिटलीकरण करने का निर्णय लिया है। इस रिकॉर्ड को सभी राज्य मुख्यालयों, मंडलायुक्त कार्यालयों, जिला मुख्यालयों, तहसीलों, उप-तहसीलों, पटवार खाना और डीओएलआर कार्यालयों में स्कैन किया जाएगा।

पहले चरण में 22 जिला मुख्यालयों और दो राज्य मुख्यालयों (हरियाणा सिविल सचिवालय और हरियाणा नया सचिवालय, चंडीगढ़) में आधुनिक राजस्व रिकॉर्ड रूम (एमआरआरआर) स्थापित किए गए हैं। दूसरे चरण में तहसील, उप-तहसील, पटवार खाना के रिकॉर्ड को डिजिटलाइज़ किया जाएगा। पहले चरण में लगभग 18. 50 करोड़ रुपए के राजस्व रिकॉर्ड को डिजिटलाइज़ किया गया है।

सुरक्षित प्रक्रिया से होगा डाउनलोड

रिकॉर्ड को डिजिटलाइज़ करने के लिए तीन स्तरीय सत्यापन प्रक्रिया को फोलो किया गया है। स्कैनिंग और डिजिटलीकरण के बाद सबसे पहले विक्रेता द्वारा पूरी गुणवत्ता जांच की जाएगी और आगे की जांच के लिए रिकॉर्ड की पीडीएफ सर्वर पर अपलोड हो जाएगी। इस रिकॉर्ड की 100 प्रतिशत जांच राजस्व अधिकारियों द्वारा की जाएगी। इसके अलावा हारट्रोन अधिकारियों द्वारा 10% रैंडम जांच और अंत में संबंधित डीआरओ द्वारा रिकॉर्ड की 20 प्रतिशत रैंडम जांच की जाएगी। अत; उपर्युक्त तीन स्तरीय जांच/सत्यापन प्रक्रिया से गुजरने के बाद रिकॉर्ड सर्वर पर संग्रहीत होगा और एक सुरक्षित प्रक्रिया के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकेगा।

बायोमेट्रिक से होगी रिकॉर्ड रूम में एंट्री

आधुनिक राजस्व रिकॉर्ड रूम में फाइलों को कंप्यूटरीकृत वातावरण में बार कोड तकनीक की सहायता से विशेष रूप से निर्मित कस्टमाइज्ड हैवी ड्यूटी रैक्स में रखा जाएगा। आग जैसी किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पाउडर बेस अग्निशामक, सीसीटीवी कैमरे और स्मोक डिटेक्टर आदि का इस्तेमाल किया गया है।

अनुभव को प्राथमिकता देगी सरकार

हरियाणा सरकार राजकीय सेवाओं को और अधिक कारगर बनाने व सुचारू वितरण के ठोस प्रयास कर रही है। जिसके चलते विभिन्न विभाग अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार कर रहे हैं तथा योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा कर रहे हैं। समयबद्ध गुणवत्तापरक परिणाम प्राप्त करने के लिए व्यवस्था में योग्य एवं सक्षम सलाहकारों, पेशेवरों और विशेषज्ञों की कमी को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रमों के लिए लक्ष्यों को परिभाषित करने और विजन को हकीकत में बदलने की रणनीति तैयार होगी।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इसके लिए नेशनल इंस्टीच्यूट फार स्मार्ट गवर्नमेंट और राज्य सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। उम्मीद जताई गई कि इन प्रयासों के चलते सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अनुभव और विशेषज्ञता प्राप्त कर 'इन हाउस' क्षमताओं में वृद्धि और सुधार किया जा सकेगा।

पेपरलेस होगा विधानसभा का आगामी बजट सत्र

'आज़ादी के अमृतमहोत्सव को समर्पित रहेगा हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन अधिवेशन। यह अधिवेशन 17 दिसम्बर से आरंभ होगा। इस सत्र की अवधि कितनी होगी, यह निर्णय उसी दिन सुबह 'बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में लिया जाएगा।'

विधानसभाध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के अनुसार अब प्रदेश की विधानसभा को ई-विधानसभा बनाने जा रहे हैं। आगामी बजट सेशन में पेपरलेस विधानसभा के तौर पर काम किया जाएगा। बजट सत्र मार्च में होता है। विधानसभा को ई-विधानसभा बनाने की प्रक्रिया काफी हद तक पूरी हो चुकी है। संभावना जताई जा रही है कि शीतकालीन सत्र 21 दिसंबतर तक चलेगा।

पांच लाख विद्यार्थियों को टैबलेट देगी सरकार

सुन री बहना, सुन रे भाई, इब टैबलेट से करो पढ़ाई

जी हां, हरियाणा की मनोहर सरकार आगामी शैक्षणिक सत्र से प्रदेश के 5 लाख विद्यार्थियों को छोटा लैपटॉप यानी टैबलेट देने जा रही है ताकि उन्हें डिज़िटल पढ़ाई में कोई परेशानी न हो। योजना की शुरुआत में ये टैबलेट 11 वीं व 12 वीं कक्षा के विद्यार्थियों व 36 हजार पीजीटी को दिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कोविड काल में ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान इस तरह की जरुरत को महसूस किया गया था। वर्तमान युग वैसे भी डिज़िटल का है, भविष्य में यह प्रारूप और आगे बढ़ेगा। स्कूल कालेजों का बहुत सारा सलेबस डिज़िटल रूप में आ गया है। अधिकांश विद्यार्थी मोबाइल फोन पर पढ़ाई करते देखे जा सकते हैं।

राज्य सरकार चाहती है कि प्रदेश के विद्यार्थियों को इस तरह का अभाव महसूस न हो, वे खुलकर पढ़ाई करें और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। राज्य सरकार की ओर से उनको कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, ऐसा प्रयास रहेगा।

योजना के शुरुआती चरण में प्रदेशभर के 11वीं व 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को टैबलेट दिए जाएंगे। गत दिनों हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में कुल 23 एजेंडों के संदर्भ में करीब एक हजार करोड़ रुपए की परचेज से संबंधित फैसले लिए गए थे जिनमें से एक यह भी रहा।

सरकार ने जिन पांच लाख टैबलेट खरीदने का फैसला लिया है, वह आगामी शिक्षा सत्र से लागू हो जाएगा। इन टैबलेट को खरीदने में कुल 560 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा भविष्य में अन्य कक्षाओं के विद्यार्थियों को भी टैबलेट देने की योजना बनाएगी।

शिक्षामंत्री कंवरपाल ने कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी किसी भी तरह से प्राइवेट स्कूलों के बच्चों से कम नहीं हैं। सरकारी स्कूल के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों जैसी आबोहवा व संसाधन प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे सुपर-100 कार्यक्रम को बड़ी सफलता मिली है। इसमें 28 बच्चों का चयन आईआईटी में तथा 24 विद्यार्थियों का चयन नीट में हुआ है। नीट में चयनित 24 में से 7 विद्यार्थियों का चयन एम्स के लिए हुआ है।

-संवाद ब्यूरो

संपादकीय

लिंगानुपात में सुधार

यह पूरे हरियाणा के लिए गर्व का विषय है कि हमारा प्रदेश देश के उन प्रदेशों में शुमार हो गया है जहां गत पांच वर्षों में जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार हुआ है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5) के मुताबिक देश में एक हजार लड़कों के जन्म के मुकाबले 929 लड़कियों का जन्म हो रहा है। पिछले सर्वेक्षण, जो 2015-16 में हुआ था, के मुताबिक एक हजार लड़कों के जन्म के मुकाबले 919 लड़कियों का जन्म हो रहा था। दूसरी ओर, देश में पहली बार एक हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ज़्यादा हुई है। सर्वेक्षण के मुताबिक देश में एक हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1020 है। ऐसा लिंगानुपात विकसित देशों में पाया गया है।

सर्वेक्षण के इस चरण में जिन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सर्वेक्षण में शामिल किया गया, उनमें अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखण्ड, मध्यप्रदेश, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ओड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सहयोग से गर्भधारण पूर्व एवं प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम को अच्छे तरीके से लागू करने व अन्य उपायों के माध्यम से जन्म लिंगानुपात को पहले से बेहतर किया गया है।

दूसरी ओर, बच्चों और महिलाओं में रक्तअल्पता चिंता का विषय बना हुआ है और 14 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में आधी से अधिक महिलाओं व बच्चों में रक्त ाल्पता की समस्या बनी हुई है। चरण दो में शामिल सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों और अखिल भारतीय स्तर पर एनएफएचएस-4 की तुलना में आधे से अधिक बच्चे और महिलाएं (गर्भवती महिलाओं सहित) रक्त अल्पता से पीड़ित हैं जबकि 180 दिनों या उससे अधिक समय की गर्भवती महिलाओं द्वारा आयरन, फोलिक एसिड गोलियों की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

- डा चंद्र त्रिखा

परिवार का सहारा बनेंगे 'पहचान पत्र'

केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का मुक्कमल लाभ देने के लिए परिवार पहचान पत्र योजना मील का पत्थर साबित होने जा रही है। योजना को मूर्तरूप देने के कार्य में काफी तेजी आई है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बारे में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई परिवार पहचान पत्र बनाने की मुख्य पहल में प्रगति हुई है। यह पहल नागरिकों को पेपरलेस, फेसलेस सेवा प्रदायगी के साथ-साथ उनके 'ईज ऑफ लिविंग' में सुधार का मार्ग प्रशस्त करेगी। इस योजना का उद्देश्य अंत्योदय के मूल मंत्र पर चलते हुए अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना है।

राज्य सरकार ने लगभग 30,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश के साथ एक पाइपलाइन में प्रमुख योजनाएं/परियोजनाएं विकसित की हैं। इन परियोजनाओं को लागू करने के लिए एस.पी.वी. स्थापित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार के उपक्रम हरियाणा राज्य वित्तीय सेवा लिमिटेड को हरियाणा सतत विकास लक्ष्य आर्थिक सुधार कोष को सहायता देने और इस उद्देश्य के लिए बाज़ार से धन जुटाने का काम सौंपा गया है।

सिंगल विंडो पोर्टल से सेवाएं

हरियाणा उद्यम और रोज़गार नीति-2020 के अलावा, वेयरहाउस और लॉजिस्टिक्स, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा और फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्रों में निवेशकों की विशिष्ट ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट नीतियां भी शुरू की गई हैं। इन्वेस्ट हरियाणा सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से 25 से अधिक विभागों की औद्योगिक और व्यवसाय से संबंधित 150 से अधिक सेवाएं दी जा रही हैं। इस पोर्टल के माध्यम से तीन लाख से अधिक सेवाएं दी जाती हैं। राज्य में निवेशकों के हित में की गई अन्य प्रमुख पहलें भूमि अधिग्रहण, भवन नक्शों की स्वीकृतियों और केंद्रीय निरीक्षण प्रणाली से संबंधित हैं। हरियाणा ने भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुर्नस्थापना में उचित मुआवज़े और पारदर्शिता का अधिकार विधेयक, 2021 पारित किया है, जो भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सरल बनाकर विकास परियोजनाओं में तेज़ी लाने का काम करेगा।

चार स्तंभों पर आधारित रणनीति

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के संकट के समय में कुशल वित्तीय प्रबंधन से हरियाणा सरकार वर्ष 2020-21 की पांच प्रतिशत स्वीकृत सीमा के मुकाबले राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी का 2.90 प्रतिशत बनाए रखने में सक्षम रही है। राज्य ने अपनी ऋण देयता को भी सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है, क्योंकि 2020-21 में जीएसडीपी अनुपात का ऋण 23.27 प्रतिशत था। हरियाणा की अर्थव्यवस्था के पुनः उत्थान के लिए रणनीति 'वी आकार' की रिकवरी प्राप्त करने और अर्थव्यवस्था के पुनः उत्थान का मार्ग प्रशस्त करने के लिए हमने चार स्तंभों पर आधारित रणनीति बनाई है।

कारोबार के अनुकूल माहौल

- हरियाणा सरकार ने निवेशकों को राज्य के कारोबार अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र की ओर आकर्षित करने की दिशा में कई कदम उठाए हैं।
- भारत सरकार द्वारा निर्देशित सुधारों को लागू करने में हरियाणा अग्रणी रहा है। राज्य ने बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (2020-21) के तहत अनिवार्य सभी 301 सुधारों को पूरा कर लिया है।
- इन सुधार क्षेत्रों में भूमि पंजीकरण, भवन नक्शों का अनुमोदन, स्थानीय निकायों के अनुमोदन, बिजली और पानी (उपयोगी सेवाएं) कनेक्शन, अनुबंध प्रवर्तन, सिंगल विंडो डेस्क की स्थापना, निवेश सुविधा हेल्पडेस्क को मज़बूत करना, क्षेत्रवार लाइसेंस और कई अन्य अनुमोदन शामिल हैं।

-संवाद ब्यूरो

हरियाणा को स्वच्छता सर्वेक्षण में स्टेट अवार्ड

हरियाणा ने स्वच्छता के मामले में एक बार फिर बाजी मारी है। प्रदेश को स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में एक स्टेट अवार्ड मिला है। इसके अलावा दो शहरों को 'गारबेज-फ्री सिटी' व एक शहर को 'सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज' के अवार्ड से नवाजा गया।

प्रदेश के 12 नगर निकायों को 'ओडीएफ प्लस-प्लस' तथा अन्य 43 नगर निकायों को 'ओडीएफ प्लस' से प्रमाणित किया गया है।

नगर निगम रोहतक तथा नगर निगम गुरूग्राम को 'गारबेज-फ्री सिटी' का अवार्ड मिला। नगर निगम गुरूग्राम को 'सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज' के अवार्ड मिला है।

केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के 12 नगर निकायों को 'ओडीएफ प्लस-प्लस' से प्रमाणित किया गया है, इनमें गुरूग्राम, करनाल, रोहतक, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, हिसार, नीलोखेड़ी, पानीपत, घरौंडा, रेवाड़ी तथा रादौर शामिल हैं। उक्त नगर निकायों के अलावा अन्य 43 नगर निकायों को 'ओडीएफ प्लस' से प्रमाणित किया गया है।

स्वच्छ सर्वेक्षण-2020 में भी हरियाणा राज्य ने स्वच्छता के मामले में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। गत वर्ष स्वच्छ सर्वेक्षण-2020 के दौरान पूरे देश में जहां 6 शहरों को 5-स्टार, 65 शहरों को 3-स्टार तथा 70 शहरों को 1-स्टार से प्रमाणित किया गया था वहीं हरियाणा के नगर निगम करनाल ने 3-स्टार रेटिंग तथा नगर निगम रोहतक को 1-स्टार रेटिंग प्राप्त हुई थी। इनके अलावा, 13 शहरों, जिनमें गुरुग्राम, करनाल, रोहतक, अंबाला, गन्नौर, पंचकूला, यमुनानगर, पानीपत, घरौंडा, रेवाड़ी, सांपला, हिसार तथा रादौर शामिल हैं, को 'ओडीएफ प्लस-प्लस' तथा 16 शहरों को 'ओडीएफ प्लस' घोषित किया गया था।

सलाहकार संपादक :	डा. चंद्र त्रिखा
सह संपादक :	मनोज प्रभाकर
संपादकीय टीम :	संगीता शर्मा, सुरेंद्र मलिक
संपादन सहायक :	सुरेंद्र बांसल
चित्रांकन एवं डिज़ाइन :	गुरप्रीत सिंह
डिजिटल सपोर्ट :	विकास डांगी

खेलो इंडिया की तैयारी

खेलो इंडिया यूथ गेम्स-2021 हरियाणा के पंचकूला, अंबाला, शाहाबाद, चंडीगढ़ और दिल्ली राज्य में होंगे। हरियाणा सरकार ने इसके लिए प्रबंधन समिति गठन करने का निर्णय लिया है। समिति इन खेलों के लिए आवास, खानपान, परिवहन, समारोहों, आयोजन दिवसों और खेल उपकरणों की खरीद के संबंध में 25 खेल व्यवस्थाओं की निगरानी करेगी। समिति की अध्यक्षता खेल एवं युवा मामलों के राज्य मंत्री संदीप सिंह करेंगे। खेलो इंडिया का आयोजन 5 से 14 फरवरी, 2022 के बीच होगा।

मुख्यमंत्री मनोहरलाल की अध्यक्षता में खेलो इंडिया यूथ गेम्स-2021 की तैयारी की समीक्षा के लिए सह-समन्वय आयोजन समिति की आयोजित दूसरी बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। खेल और युवा मामलों के राज्य मंत्री, श्री संदीप सिंह भी बैठक में मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को खेल के बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुव्यवस्थित करने के भी निर्देश दिए हैं। बैठक में मुख्यमंत्री को बताया गया कि विभिन्न खेल परिसरों, हॉकी स्टेडियम और बैडमिंटन हॉल, ऑडिटोरियम और एथलेटिक स्टेडियम के विकास कार्य पूरे होने वाले हैं और दिसंबर तक बनकर तैयार हो जाएंगे। इनकी तैयारियों की साप्ताहिक समीक्षा की जा रही है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स-2021 में पंचकूला से यमुनानगर के बीच साइकिलिंग प्रतियोगिता होगी।

थीम सॉंग तैयार

कार्यक्रम का शुभंकर 'धाकड़' और थीम सॉन्ग तैयार कर लिया गया है। इसके लॉन्च और प्रमोशन समारोह की तारीखें जल्द तय की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने खेल विभाग में इंजीनियरिंग विंग स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाने के भी निर्देश दिए हैं। एचएसवीपी द्वारा एक जनवरी, 2022 से 10 खेल परिसरों को खेल विभाग को सौंप दिया जाएगा।

-संवाद ब्यूरो

स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंबाला में स्थापित किए जा रहे कैंसर अस्पताल का दौरा किया। सिविल सर्जन डा. कुलदीप के साथ उन्होंने वहां लगाई जा रही अत्याधुनिक मशीनों का निरीक्षण किया।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बाल दिवस के अवसर पर गुरुग्राम में श्रवण एवं वाणी निशक्तजन कल्याण केंद्र द्वारा तैयार की गई पांचवीं कक्षा तक की इंडियन साइन लैंग्वेज की पाठ्यपुस्तिकाओं का विमोचन किया।

मनोज प्रभाकर

बदलते गांव बदलता हरियाणा
गांव पर्यटन

प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, क्योंकि यह न केवल रोजगार प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है बल्कि निश्चित रूप से राज्य के राजस्व और सकल घरेलू उत्पाद के ग्राफ में भी वृद्धि करेगा।

दैनिक जीवन की नीरसता को छोड़कर, फार्म टूरिज्म पर्यटकों व आगंतुकों को साधारण ग्रामीण जीवन से जुड़ने और उसका आनंद लेने की दिशा में पहला कदम है। संशोधित फार्म पर्यटन नीति में फार्म मालिकों और पर्यटकों दोनों के लिए अधिक विकल्पों और सुविधाओं को समाहित किया है। फार्म मालिक अब नीति के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के साथ अपने व्यवसाय को बड़े और लचीले वाणिज्यिक स्तर पर विस्तार कर सकते हैं। दूसरी ओर पर्यटक अब सुरक्षा के साथ वास्तविक ग्रामीण जीवन का आनंद ले सकते हैं। यह ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद करेगा और हरियाणा को पर्यटन मानचित्र पर महत्वपूर्ण गंतव्य के रूप में अलग पहचान स्थापित करने में लाभदायक सिद्ध होगा।

कुरुक्षेत्र के दर्शनीय स्थल

कुरुक्षेत्र के तीर्थ एवं पर्यटन स्थलों को दर्शनीय स्थलों के रुप में विकसित किया जाएगा। इस योजना के तहत ही गुमथला गढु के सोमतीर्थ, भौर सैंयदा के भूरीश्रवा तीर्थ, थानेसर के कालेश्वर तीर्थ, गांव मांगना के सप्तसास्वत तीर्थ का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसके अलावा, सरकार द्वारा श्रीकृष्णा सर्किट के तहत, ब्रहमसरोवर, सन्निहित सरोवर, गीतास्थली ज्योतिसर और नरकरतारी तीर्थ व पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए 97.50 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है और सभी कार्य पूरे होने की स्थिति में पहुंच गए है।

सरस्वती नदी का जीर्णोद्धार

राज्य सरकार ने सरस्वती नदी के जीर्णोद्धार के लिए हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश की राज्य-सीमा पर स्थित सोम नदी पर एक बांध बनाने का निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस बांध के निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र दे दिया है तथा अब सिंचाई विभाग ने केंद्रीय जल आयोग के पास बांध के डिजाइन के लिए केस भेज दिया है ताकि आगे की कार्यवाही की जा सके।

आदि बद्री के स्थान पर सोम नदी के नीचे की ओर एक बैराज भी प्रस्तावित किया गया है जिससे भूमिगत पाइप लाइन के माध्यम से गांव रामपुर हेरिया, रामपुर कांबियान और छिल्लौर में सरस्वती जलाशय में जल प्रवाह होगा। पर्यटन मंत्री कंवरपाल का अनुमान है कि यह पूरा क्षेत्र पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनेगा।

माधोगढ़ किला व रानी तालाब

महेंद्रगढ़ जिले के ऐतिहासिक स्थलों को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य सरकार इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। माधोगढ़ किला पर रानी तालाब के पुनर्निर्माण का कार्य हो चुका है तथा रानी महल का कार्य भी अंतिम चरण में है। इस काम पर 9 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इन दोनों पर्वतों पर पर्यटन की काफी संभावनाएं हैं। ढोसी पर्वत को जहां तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने की योजना है, वहीं माधोगढ़ किला पर अधिक से अधिक पर्यटन लाने के लिए आने वाले समय में माधोगढ़ के राजा महल का भी निर्माण की योजना है।

मोरनी से कलेसर तक पर्यटन

राज्य सरकार द्वारा मोरनी क्षेत्र में हर्बल पार्क बनाया जा रहा है जिसमें विदेशों से भी रिसर्च करने के लिए वैज्ञानिक आंएगे और किसानों को भी लाभ होगा। काला आम्ब के सतकुम्भा मंदिर क्षेत्र, त्रिलोकपुर मंदिर, कलेसर मंदिर, पंचमुखी मंदिर बसातियावाला, कपाल मोचन क्षेत्र को विकसित करने के कदम उठाए गए है और बाबा बंदा सिंह बहादुर की राजधानी लौहगढ़ को भी विकसित किया जा रहा है। कलेसर में नौकायन को बढ़ावा दिया जाएगा तथा मोरनी से कलेसर तक का क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से एक अच्छा क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव है।

फार्म टूरिज्म को नया स्वरूप

पर्यटन की दृष्टि से अपने हरे भरे वातावरण के लिए जाना जाने वाला पंचकूला उन आगंतुकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण के रूप में उभरा है, जो पंचकूला से गुजरने वाली खूबसूरत पर्वत श्रृंखलाओं का आनंद लेना चाहते हैं। इसलिए देश और दुनिया भर में हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देने के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने होम स्टे और फार्म टूरिज्म नीतियों का भी शुभारंभ किया है। इससे पर्यटकों को होम स्टे के रूप में होटलों का एक शानदार विकल्प मिल सकेगा, जिससे उन्हें स्थानीय परिवारों के साथ उनके घरों में रहने और स्थानीय संस्कृति व व्यंजनों का अनुभव मिल सकेगा।

हरियाणा में फार्म टूरिज्म को भी एक नया स्वरूप दिया जा रहा है, जहां अधिक से अधिक शानदार फार्मों को सूची में जोड़ा गया है। अब पर्यटक छुट्टियों का आनंद लेने के लिए अपने पसंदीदा फार्म हाउस का चुनाव कर सकते हैं। यह स्थानीय फार्म मालिकों और ग्रामीणों को आजीविका के अवसर प्रदान करने में मदद करेगा। कौशल विकास मिशन के तहत पात्र चयनित होम-स्टे मालिकों को हरियाणा पर्यटन द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

स्वप्रेरित आदर्श ग्राम योजना
सुई गांव का विकास देखने पहुंचे राष्ट्रपति

साढ़े पांच हजार की आबादी वाला आदर्श गांव सुई भिवानी जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर है। मुंबई के कारोबारी एवं गांव के मूल निवासी किशन जिंदल ने इस गांव को आदर्श गांव बनाया है। गांव इतना सुंदर बन पड़ा है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गत दिनों इसे देखने के लिए यहां पहुंच गए।

गांव में करीब 900 परिवार हैं। उद्योगपति किशन जिंदल ने इसे गोद ले रखा है। उन्होंने करोड़ों रुपए लगाकर गांव का विकास किया है। उन्होंने अपनी मां महादेई के नाम पर पार्क बनवाया है। गांव मानो टूरिस्ट पैलेस बनकर उभर रहा है। गांव में कुल आठ छोटे-बड़े पार्क हैं। एक बड़ा ऑडिटोरियम है, जिसमें 500 लोगों के एक साथ बैठने की व्यवस्था है। गांव में आरओ सिस्टम लगाने का काम जारी है। बरसात का पानी इक्ट्ठा करने के बाद शुद्ध करके इसे सप्लाई किया जाएगा। बताते हैं गोद लेने के बाद किशन जिंदल इस गांव पर 25 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च कर चुके हैं।

गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है, इस पर नियमित कार्य होता है। गांव की तमाम गलियां पक्की व नई हैं। निकासी के पानी की समुचित व्यवस्था की

गई है। गांव में हरियाली के लिए अनेक पेड़-पौधे लगाए गए हैं। एक सुंदर झील का निर्माण कराया गया है जिसमें नौकाविहार की सुविधा है। गांव में जो सरकारी भवन हैं सब नए बनवाए गए हैं। सरकारी स्कूल पुराना अवश्य है लेकिन नए से कम नहीं है। स्कूल में आधुनिक सुविधाओं वाली साइंस लैब है। ग्रामीण बताते हैं कि कोरोना के कारण विकास कार्य रुक गया था। अब गांव में बड़ा अस्पताल बनाने की योजना है। गांव में एक बड़ा भवन बनाया गया है जो व्हाइट हाऊस जैसा लगता है।

100 रुपए उधार लेकर गया था मुंबई

करीब 80 वर्षीय किशन जिंदल आज राष्ट्रपति के कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे। किशन के पिता परमेश्वर जिंदल गांव में ही खेतीबाड़ी करते थे। वे काफी गरीब थे। किशन अपनी मां महादेई की मौत के बाद 1962 में गांव के एक परिवार से 100 रुपए उधार लेकर मुंबई गए थे। मुंबई में उनका काम ऐसा चला कि वे नामी उद्योगपति बन गए। वे बड़े आदमी जरुर बने लेकिन गांव के प्रति मोह बरकरार रहा। वे साल में एक बार अपनी कुलदेवी की पूजा के लिए मुबंई से गांव अवश्य पहुंचते हैं।

205 लोगों ने अपने पैतृक गांव में विकास कार्य करवाने की इच्छा जताईः सीएम

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का हरियाणा की धरती पर स्वागत करते हुए कहा कि ये सौभाग्य की बात है कि आदर्श ग्राम योजना पर मुहर लगाने के लिए खुद राष्ट्रपति हरियाणा आए हैं। इससे हरियाणा के ग्रामीण विकास को नई ऊर्जा मिलेगी।

मुख्यमंत्री स्वप्रेरित आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत विकसित भिवानी के आदर्श गांव सुई के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। इस कार्यं म में देश की प्रथम महिला सविता कोविंद, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वप्रेरित आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत गांवों का विकास हो रहा है। उन्होंने बताया कि इसी तरह गांवों से निकलकर देश और विदेश में जा चुके 205 लोगों ने अपने पैतृक गांव में विकास कार्य करवाने की इच्छा जताई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की संपत्तियों का पंजीकरण करने के लिए 'स्वामित्व योजना' शुरू की गई है। स्वामित्व योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में एक और जहां लोगों के आपसी झगड़े खत्म होंगे, वहीं विकास के नए मार्ग भी प्रशस्त होंगे।

मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव एवं हरियाणा रोलर स्केटिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. अमित अग्रवाल ने पंचकूला में आयोजित 35वीं स्टेट रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में विजेताओं को पदक देकर सम्मानित किया।

कम खर्च में अधिक लाभ देती है सरसों की फसल

सरसों रबी में उगाई जाने वाली फसलों में एक महत्वपूर्ण फसल है। सरसों वर्गीय फसलों के तहत तोरिया, राया, तारामीरा, भूरी व पीली सरसों आती हैं। हरियाणा में सरसों मुख्य रूप से रेवाड़ी, महेन्द्रगढ़, हिसार, सिरसा, भिवानी व मेवात जिलों में बोई जाती है। किसान सरसों उगाकर कम खर्च में अधिक लाभ कमा रहे हैं। अगेती सरसों में चित्तकबरा कीड़ा (धोलिया) अधिक हानि पहुंचाता है तथा पछेती सरसों में चेपा का अधिक प्रकोप रहता है। इसलिए किसानों को इन फसलों की तापक्रम व मौसम की अनुकूल परिस्थिति को ध्यान में रखकर बिजाई करनी चाहिए।

किसान सरसों के कीटों को अच्छी तरह पहचान कर उनका आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बी.आर. काम्बोज ने कहा है कि किसान विश्वविद्यालय से जुड़कर और वैज्ञानिक सलाह लेकर समय-समय पर अपनी फसलों संबंधी जानकारी हासिल कर सकते हैं और अपनी फसलों की पैदावार में बढ़ोतरी कर सकते हैं। आनुवांशिकी एवं पौध प्रजनन विभाग के अध्यक्ष डॉ. एस.के. पाहुजा के अनुसार अगेती व पछेती सरसों की फसल में कई प्रकार के कीटों का प्रकोप हो सकता है, जिनकी किसान समय से पहचान कर रोकथाम कर

फसल से अधिक पैदावार हासिल कर सकते हैं। डॉ. रामअवतार व डॉ. दलीप कुमार ने बताया कि सभी कीटनाशकों का छिड़काव सदैव सायंकाल को 3 बजे के बाद करें ताकि मधुमक्खियों को कोई नुकसान न हो, जो उपज बढ़ाने में सहायक होती हैं।

चित्तकबरा कीट या धोलिया : यह सरसों का मुख्य कीट है जिसके शिशु व प्रौढ़ पौधों से रस चूसकर नुकसान पहुंचाते हैं। इसके शिशु व प्रौढ़ अण्डाकार होते हैं जिनके उदर पर काले भूरे धब्बे होते हैं। यह पौधों के विभिन्न भागों से रस चूसकर नुकसान पहुंचाते हैं जिसके कारण पौधे की पत्तियों पर सफेद धब्बे बन जाते हैं। इसलिए इस कीट को धोलिया भी कहते हैं। इसके अधिक आक्रमण से पौधे सूख जाते हैं। कीट का प्रकोप फसल की प्रारंभिक अवस्था व कटाई के समय अधिक होता है। अधिक सर्दी में वयस्क अवस्था में निष्क्रिय रहता है। फसल उगने के समय इस कीट का आक्रमण होने पर 200 मि.ली. तथा फसल कटाई के समय होने पर 400 मि.ली. मैलाथियान 50 ई.सी. का 200 व 400 लीटर पानी प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें।

सरसों की आरा मक्खी : यह हाइमेनोप्टरा वर्ग का एकमात्र हानिकारक कीट है जो फसल को नुकसान पहुंचाता है। इस कीट की गहरे रंग की सूंडी पत्तियों में छेद करके तथा नई प्ररोह को काटकर हानि पहुंचाती है। इसकी सूण्डी दिन के समय छिपी रहती है। छेड़ने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे मरी पड़ी हो। इसके उदर के ऊपरी भाग पर पांच काले रंग की पट्टियां होती हैं।

सरसों का माहू/चेपा/अल : इस कीट के शिशु व प्रौढ़ समूह में रहकर पौधों पर आक्रमण करते हैं जिससे फलियां व तना चिपचपा हो जाता है। फलियों में दाने नहीं बन पाते हैं और दाने बनते भी हैं तो कमज़ोर बनते हैं। यह कीट हल्के हरे रंग का होता है। जो कभी पंख रहित व कभी पंख सहित होता है जो फरवरी-मार्च माह में उड़ते भी दिखते हैं। इस कीट की संख्या दिसम्बर से मार्च माह तक प्रचुर मात्रा में होती है। कीट बिना निषेचन के ही सीधे शिशु पैदा करते हैं।

रोकथाम : इनकी रोकथाम के लिए किसान सरसों फसल की बिजाई अधिक देरी से न करें और आक्रमण होने पर कीटग्रस्त टहनियों को तोड़कर नष्ट कर दें। यदि कीट का आर्थिक स्तर 10 प्रतिशत पुष्पित पौधों पर 9-19 कीट या औसतन 13 कीट प्रति पौधा होने पर 250 से 400 मि.ली. (मिथाइल डेमेटान मेटासिस्टॉक्स) 25 ई.सी. या डाइमेथोऐट (रोगोर) 30 ई.सी. को 250 से 400 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ छिड़काव करें। आवश्यकता पड़ने पर दूसरा छिड़काव 15 दिन बाद करें।

सुरंग बनाने वाली सूण्डी : इस कीट की सूंडियां पत्तियों में सुरंग बनाकर हरे पदार्थ को खाती हैं। पत्ता सूर्य की तरफ करने पर कीट साफ दिखाई देता है। पौधे कमजोर हो जाते हैं तथा उत्पादन पर भी असर पड़ता है। माहू/अल की रोकथाम हेतु बताए गए कीटनाशक से इसे आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है।

बालों वाली सूंडियां : इन सूंडियों का आक्रमण अक्तूबर से नवंबर में अधिक होता है। आरंभ में यह सूंडियां सामूहिक रूप में रहकर फसल की पत्तियों को खा जाती हैं। बड़े होने पर अकेले रहकर सारे खेत में फैल जाती हैं। ऐसी पत्तियां जिन पर सूंडियां समूह में हों उन्हें तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए।

-संवाद ब्यूरो

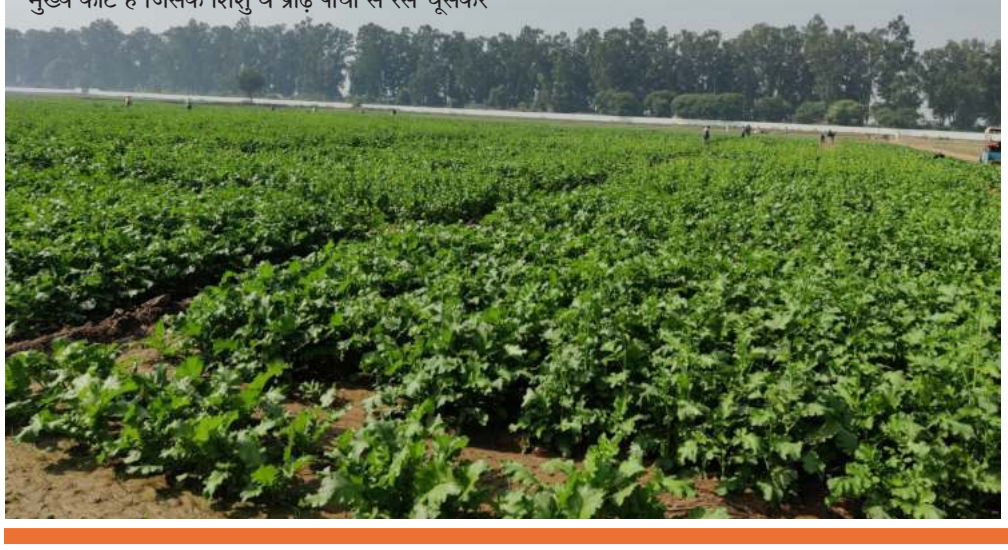

बागवानी है फ़ायदे की खेती

किसानों का रूझान धीरे-धीरे फसल विविधिकरण की तरफ बढ़ रहा है। कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाने को लेकर किसान उन फसलों की खेती कर रहे हैं जिनकी मार्केट में ज्यादा मांग है। जिला नूह के गांव मड़ी के प्रगतिशील किसान तैय्यूब हुसैन की जो 6 एकड़ में बेर की खेती करके प्रति वर्ष लाखों रूपये की कमाई कर रहे हैं। तैय्यूब हुसैन ने बताया की उन्होंने 10 वर्ष पूर्व बागवानी में रूचि लेना प्रारंभ किया। शुरूआती दौर में बागवानी कष्टदायी नजर आई। उन्होंने जिला जींद से कुछ फलों के पौधे लिये व करीब तीन एकड़ में पौधारोपण किया। पौधों के तैयार होने पर जब चिंतन किया तो बागवानी लाभकारी नज़र आई। इसके बाद तीन वर्ष पूर्व तीन एकड़ में बेर की खेती का विस्तार किया। वे बागवानी के साथ-साथ पशुपालन में रूचि लेते हैं।

हुसैन ने बताया की बारिश के समय में वे पानी का संग्रह कर लेते हैं जिसका प्रयोग वर्ष भर बागवानी के लिए करते हैं। हुसैन ने अपने खेत में पानी का बड़ा कुंड बनाया हुआ है। कहते हैं एक एकड़ में उन्होंने 10-10 चंदन, अंजीर, शहतुत, जामुन के पेड़ भी लगा रखें हैं। बागवानी में खर्च निकाल कर वे कभी 80 हजार तो कभी उससे ज्यादा कमाई कर लेते हैं। बागवानी के लिए वे दो वर्ष पूराना गोबर जहां खेत में इस्तेमाल करते हैं वहीं बीमारी से पेड़ों को बचाने के लिए कम से कम दो या तीन बार सुपर किलर का स्प्रे भी करते हैं।

हुसैन ने बताया कि बेरों का सीजन मुख्य तौर पर जनवरी के माह में होता है। अब बेरों का रंग बदल रहा है। पीला हो रहा है। चने के दाने के समान दाना आया हुआ है। कई स्थानों पर फूल आये हुए हैं। उनके अनुसार पूरी तरह से तैयार होने पर एक बैर का वजन 70 से 75 ग्राम होता है। उनके अनुसार अब की बार बागवानी में अच्छी संभावनाएं नजर आ रही है। भरपूर बारिश से फसल लहरा रही है।

जिला बगाबवानी अधिकारी डॉ. दीन महोमद खान ने बताया कि सरकार बाग लगाने पर किसानों को 40 प्रतिशत सब्सिडी देती है जिसमें पहले साल 3,400 रुपए व अगले दो सालों में 1,700- 1,700 रुपए पौधे खरीदने व दवा आदि के लिए प्रदान करती है।

-सुरेन्द्र सिंह मलिक

जैविक खेती नितांत आवश्यक

मानव जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए नितांत आवश्यक है कि प्राकृतिक संसाधन प्रदूषित न हों, शुद्ध वातावरण रहे एवं पौष्टिक आहार मिलता रहे। इसके लिए हमें जैविक खेती की कृषि पद्धतियां को अपनाना होगा जोकि हमारे प्राकृतिक संसाधनों एवं मानवीय पर्यावरण को प्रदूषित किए बगैर समस्त जनमानस को खाद्य सामग्री उपलब्ध करा सकें।

प्रदेश सरकार किसानों के हितों के लिए हर संभव कदम उठाने को कृत संकल्प है और जैविक खेती आज के समय की आवश्यकता है। गौशालाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए गाय के गोबर से जैविक खाद तैयार करने और गौमूत्र के प्रासंगिक उपयोग के लिए अनुसंधान पर अधिक ज़ोर दिया जा रहा है। प्रदेश के किसानों को जैविक खेती अपनाने एवं गौशालाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

किफ़ायती दामों में उपलब्ध

रासायनिक खादों से जमीन की उपजाऊ शक्ति कम होने के साथ-साथ फसलों की पैदावार भी कम होती जाती है और पर्यावरण भी दूषित होता है जिससें बिमारियों के फैलने का खतरा रहता है। इसलिए किसानों को अपनी फसलों में जैविक खाद को बढ़ावा देना चाहिए। यह खाद निश्चित तौर पर रासायनिक डीएपी से काफ़ी सस्ती व ज़्यादा कामयाब साबित हो सकती है।

जैविक प्रोम का सर्टिफिकेशन किया जाए : कृषि मंत्री

प्रदेश के किसानों को जैविक खेती अपनाने एवं गौशालाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जायेंगे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जे.पी.दलाल ने कहा कि गौ अनुसंधान केंद्र में तैयार और डीएपी के विकल्प जैविक प्रोम का सर्टिफिकेशन किया जाए। इस खाद के मानक प्रमाणित होने पर हरियाणा सरकार प्रमाणिक तौर पर तैयार खाद को किसानों तक पहुंचाएगी। यह जैविक खेती में एक जबरदस्त क्रांति का काम करेगा।

-संवाद ब्यूरो

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, योजना के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों में मसूर व चने के बीज का वितरण व इनके प्रदर्शन-प्लांट एवं सूक्ष्म तत्व, जिप्सम, जैविक खाद, खरपतवारनाशी स्प्रे पम्प आदि किसानों को अनुदान पर दिये जा रहे हैं।

स्वामी ओमानंद सरस्वती पुरातत्व संग्रहालय समिति, गुरुकुल झज्जर में एक संग्रहालय के निर्माण की योजना है। इस संग्रहालय में स्वामी ओमानंद द्वारा संरक्षित पुरातात्विक महत्व की लगभग दो लाख वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाएगा।

गोवंश अनुसंधान केंद्र पिंजौर

संगीता शर्मा

कामधेनु गोशाला सेवा सदन पिंजौर स्थित अनुसंधान केंद्र द्वारा गाय के गोबर से प्राकृतिक पेंट, गमले, डीएपी का विकल्प 'प्रोम' व गोमूत्र से फिनाइल बनाया जा रहा है। हालांकि इनकी मान्यता के लिए प्रयोगशालाओं की जांच रिपोर्ट शेष है। हरियाणा गौ सेवा आयोग के मार्गदर्शन में यह पहली गौशाला है जिसमें खादी इंडिया के तकनीकी सहयोग से गाय के गोबर से बनने वाले प्राकृतिक पेंट प्लांट की स्थापना की गई है। बताया जाता है कि यह पेंट रसायन मुक्त व बदबूरहित है, इससे कीट-मकोड़े नहीं आएंगे। नकारात्मक ऊर्जा दूर रहेगी।

एंब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी (ईटीटी) से सात गायों में देसी गोवंश का भ्रूण प्रत्यारोपित करवाए गए हैं। हरियाणा में गौवंश की नस्ल सुधार कार्यक्रम यह तकनीक मिल का पत्थर साबित होगी। इसमें साहीवाल नस्ल की बछड़ियां पैदा होगी, जो कि 18-20 प्रति लिटर प्रतिदिन दूध देंगी। गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, लुधियाना (गड़वासु) के डॉक्टर्स की टीम ने सात गायों का एंब्रियो ट्रांसफर किया था। अभी 30 गायों का निःशुल्क एंब्रियो ट्रांसफर किया जाएगा और उसके बाद प्रति एंब्रियो ट्रांसफर की कीमत 30,000 रुपए होगी।

जैविक खाद

अनुसंधान केंद्र में गाय के गोबर से डीएपी के विकल्प के रूप में प्रोम (फास्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर) पर प्रयोग, मानकीकरण एवं प्रमाणीकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। यह खाद किसानों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। इस खाद से भूमि अधिक उपजाऊ बनेगी और पैदावार में बढ़ोतरी होगी।

फिनाइल

गोमूत्र से बनने वाले गौतत्व फिनाइल पर प्रमाणीकरण एवं मानकीकरण का कार्य चल रहा है। गौतत्व फिनाइल के सैंपल में टेस्ट के दौरान आईआईटी रूड़की की प्रयोगशाला में 99.99 % वायरस नाशक होने का पुष्टिकरण किया गया है। हरियाणा में कई गौशालाएं इस फिनाइल को बनाकर बेच रही हैं। प्रमाणीकरण फिनाइल के फार्मूले को डिवलेप कर इच्छुक गौशालाओं को दिया जाएगा।

गमले

गाय के गोबर से बने गमलों पर अनुसंधान कार्य जारी है। इसके सफल होने पर प्रदेश के बागवानी विभाग और नर्सरी में लगने वाली करोड़ों पॉलीथिन से छुटकारा मिलेगा। इस तरह के गमले पर्यावरण की सुरक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण साबित होंगे ही, साथ ही पौधों को कई महीनों की खाद देने का कार्य भी करेंगे। एक-डेढ़ साल से गमले बनाएं जा रहे हैं। अभी वन विभाग, हरियाणा द्वारा टेस्टिंग के लिए लगभग 12,000 गमलों में ऑर्डर आया है और यदि यह सफल साबित होते है तो वन विभाग हरियाणा द्वारा प्रति वर्ष तीन से चार करोड़ प्रयोग होने वाले गमले अनुसंधान केंद्र से खरीदें जाएंगे।

दीपक व मूर्तियां

हरियाणा गौ सेवा आयोग के प्रोत्साहन से प्रदेश की अनेक गोशालाओं में दीपावली मनाने हेतु गाय के गोबर से लाखों दीपक और गणेश, लक्ष्मी, राधा कृष्ण जी की मूर्तियां भी बनाई गई। जिसकी बाज़ारों में अच्छी ख़ासी मांग रही। गत वर्ष दीवाली के अवसर पर दीपक व मूर्तियां बनाने व बेचने की पहल की गई थी और ख़ासी आमदनी हुई। इसको देखते हुए ही इस वर्ष हरियाणा की अलग-अलग गौशालाओं द्वारा लाखों की संख्या में मूर्तियां व

दीये बनाकर बहुत लाभ कमाया।

गौवंश में सुधार

हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग का कहना है कि प्रदेश सरकार के गौ कल्याण हेतु किए गए कार्यों का ही परिणाम है कि गत सात वर्षों में हरियाणा में गौशालाओं की संख्या 270 से बढ़कर आज 585 हो गई है। सात वर्ष पहले गौशालाओं में दो लाख गौवंश जीवनयापन कर रहा था। लेकिन आज करीब 40 लाख 50 हजार गौवंश इन गौशालाओं में मौजूद है। पिछले वर्षों में 330 गौशालाओं में 'मुख्यमंत्री जगमग योजना' के तहत हरियाणा गौ सेवा आयोग द्वारा अक्षय ऊर्जा विभाग के सहयोग से सोलर प्लांट लगवाए गए है।

गौशालाओं को बनाया जा रहा आत्मनिर्भरः सीएम

हरियाणा गौ सेवा आयोग की अधिसूचना 2010 और गठन वर्ष 2013 में हुआ था। लेकिन माननीय मनोहर लाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद गोपाष्टमी नवंबर 2015 में सक्रिय रूप प्रदान किया गया। सात वर्षों में हरियाणा गौ सेवा आयोग के माध्यम से लगभग 100 करोड़ रुपए प्रदेश की गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने व गौ चारे हेतु गौ कल्याण राशि के रूप में अनुदान स्वरूप दिया गया। इस वित्त वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट में प्रदेश में गौ कल्याण राशि को बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए कर दिया गया।

इज़राइली तकनीकी से समृद्ध होता कृषि क्षेत्र

भारत-इज़राइल परियोजना के तहत बागवानी विभाग हरियाणा की ओर से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड एक्सीलेंस विलेज पर तीन दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में देश के 23 राज्यों के लगभग 80 से 100 अधिकारियों को इस्त्राइली विशेषज्ञों द्वारा बागवानी की विभिन्न तकनीकों से अवगत कराया गया। इज़राइली विशेषज्ञ उरी रुबिनस्टीन माशव, हरियाणा राज्य बागवानी विकास के मिशन निदेशक हरदीप सिंह और महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल के कुलपति समर सिंह ने दीप प्रज्ज्वलित कर तीन दिवसीय सम्मेलन का शुभारंभ किया।

हरदीप सिंह ने कहा कि बागवानी में विविधिकरण को प्रेरित करने और किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए, हरियाणा सरकार ने 'मेरा पानी-मेरी विरासत', 'भावांतर भरपाई योजना', 'मुख्यमंत्री बगवानी बीमा योजना' जैसे कई नए कार्यक्रम, पैकेज और योजनाएं शुरू की हैं। 'फसल अवशेष प्रबंधन', 'हर खेत-स्वस्थ खेत' आदि शुरू किए गए। प्रतिभागियों को

संबोधित करते हुए कुलपति प्रोफेसर समर सिंह ने कहा कि राज्य में बागवानी का क्षेत्र पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। किसान परंपरागत खेती की जगह बागवानी की ओर बढ़ रहे हैं। करनाल में स्थापित किया जा रहा बागवानी विश्वविद्यालय इस कड़ी में मील का पत्थर साबित होगा।

सब्ज़ियों की खेती से आमदनी

सम्मेलन के पहले सत्र के दौरान, इज़राइल के विशेषज्ञ उरी रुबिनस्टीन, डैनियल हद्दाद और इत्जाक एस्क्वायर ने प्रतिभागियों को पौधों की सुरक्षा, नर्सरी प्रबंधन के बारे में जानकारी दी, जबकि दूसरे सत्र में इजरायल के विशेषज्ञ एरेज़ केडेम ने सब्ज़ियों व उद्यानों में सिंचाई की तकनीकों के बारे में जानकारी दी। इज़राइली विशेषज्ञों ने इस सत्र में अधिकारियों को बताया कि अगर किसान सब्ज़ियां उगाने की उन्नत तकनीक और रणनीति अपनाएंगे, तो उनकी उपज में उछाल आएगा और किसान अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं।

उत्कृष्टता केंद्र घरौंडा का दौरा

भारत में इज़राइल के राजदूत नाओर गिलोन एवं उनके प्रतिनिधिमंडल ने सब्ज़ी उत्कृष्टता केंद्र, घरौंडा, करनाल और उद्यान प्रशिक्षण संस्थान का भ्रमण किया। उन्होंने एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र, रामनगर (कुरुक्षेत्र) का भी दौरा किया। नाओर गिलोन ने इज़राइली तकनीकी से बने पॉलीहाउस में पैदा की गई रंगीन शिमला मिर्च, छोटी मिर्च, चैरी टमाटर व पार्थो कार्येन किस्म के खीरे सहित विभिन्न प्रकार के फूलों और सब्ज़ियों के उत्पादन को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। राजदूत ने कहा कि मात्र एक वर्ष में यहां के किसानों ने सब्ज़ी उत्पादन में प्रति हैक्टेयर उत्पादन क्षमता बढ़ाकर अपनी निपुण कार्यशैली और कर्मठता का परिचय दिया है।

मधुमक्खी पालन केंद्र

नाओर गिलोन और उनके प्रतिनिधिमंडल ने एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र, रामनगर (कुरुक्षेत्र) का भी भ्रमण किया। केंद्र के निदेशक डॉ. बिल्लू यादव ने कहा कि केंद्र का मुख्य लक्ष्य हरियाणा राज्य में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना है। डॉ. यादव ने बताया कि इसी कार्य के लिए दस गांवों को गोद लिया गया है। इंडो इज़राइल विलेज ऑफ एक्सीलेंस और मधुमक्खी पालन के लिए समय-समय पर केंद्र द्वारा तकनीकी सहायता दी जा रही है। सभी ने शहद प्रसंस्करण इकाई और बॉटलिंग इकाई का भी दौरा किया। **-संवाद ब्यूरो**

बागवानी की आधुनिक तकनीकों से किसानों को लाभ

हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि राष्ट्रीय कृषि सम्मेलनों के आयोजन से हम सभी सीखते हैं और बागवानी में सुधार के लिए विभिन्न देशों द्वारा अपनाए गए अनुभवों का आदान-प्रदान करते हैं। कृषि मंत्री पंचकूला में भारत-इज़राइल सम्मेलन के तीसरे दिन बागवानी से जुड़े इज़राइली प्रतिनिधिमंडल और वैज्ञानिकों को संबोधित कर रहे थे।

मंत्री जे.पी दलाल ने कहा कि हरियाणा कृषि के अलावा मछली पालन में इस्तेमाल की जाने वाली नई तकनीकों को अपनाने के लिए सभी देशों का स्वागत कर रहा है। उन्होंने किसानों को कुछ क्षेत्रों में भूमिगत जल की कमी को पूरा करने के लिए बागवानी और कम पानी की खपत वाली फसलों को अपनाने का आग्रह किया।

हरियाणा में और अधिक निवेश करेगा इज़राइल

भारत में इज़राइल के राजदूत नाओर गिलोन ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कृषि क्षेत्र में हरियाणा के साथ अपने मौजूदा निवेश समझौतों के अलावा अनुसंधान, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, एयरोनॉटिक्स क्षेत्रों में ओर मज़बूती व सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की।

उन्होंने कहा कि भारत में इज़राइल द्वारा किए गए कुल 80 प्रतिशत निवेश में से लगभग 50 प्रतिशत हरियाणा में निवेश किया गया है। अब इज़राइल का लक्ष्य हरियाणा में कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों में निवेश की अधिक संभावनाएं तलाशना है। उन्होंने कहा कि अब हम हरियाणा में 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' के बाद 'विलेज ऑफ एक्सीलेंस' की अवधारणा की ओर बढ़ रहे हैं।

अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने चालू वित्त वर्ष में अभी तक विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 881 लाभार्थियों को 585.37 लाख रुपए वित्तीय मदद दी है, जिसमें 54.95 लाख रुपए की सब्सिडी शामिल है।

किसानों के लिए अच्छी गुणवत्ता का गेंहू का बीज तैयार किया गया है। हैफेड द्वारा तैयार किया गया बीज प्रदेश के सहकारी विपणन समितियों और पैक्स के बिक्री केंद्रों पर रियायती दरों पर उपलब्ध रहेगा।

जगमग गांव, समृद्ध निगम

संगीता शर्मा

हरियाणा के गांव जैसे-जैसे जगमग होते जा रहे हैं, वितरण निगम भी समृद्ध होते जा रहे हैं। कुशल नेतृत्व व निपुण प्रबंधन की कड़ी मेहनत का परिणाम यह है कि आज प्रदेश में न केवल पर्याप्त बिजली उपलब्ध है बल्कि निगम मुनाफ़े में चल रहे हैं।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिजली कंपनियों के लाइन लॉस कम करके उन्हें लाभांश की स्थिति में लाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार के अनूठे प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि वे केंद्रीय विद्युत विभाग के सचिव को हरियाणा द्वारा इस दिशा में किए गए सराहनीय कार्यों का अध्ययन करने के लिए कहेंगी।

केंद्र को अवगत कराया।

» संरचनात्मक सुधार के अंतर्गत 'उदय योजना' के तहत राज्य सरकार डिस्कॉम के सकल वितरण एवं वाणिज्यिक घाटे को कम करने के लिए ठोस प्रयास कर रही है।

» पिछले पांच वर्षों के दौरान, सकल वितरण एवं वाणिज्यिक घाटा 2015-16 के 30.02 प्रतिशत से घटकर 2020-21 में 16.22 प्रतिशत रह गया।

» 2017-18 के दौरान, डिस्कॉम ने लक्ष्य वर्ष से दो साल पहले ही वित्तीय बदलाव हासिल कर 412 करोड़ रुपए का परिचालन/शुद्ध लाभ अर्जित किया है।

» वर्ष 2018-19 में यह लाभ 291 करोड़ रुपए और वर्ष 2019-20 में 331 करोड़ रुपए रहा।

» हरियाणा डिस्कॉम ने अगले तीन वर्षों में दस लाख स्मार्ट मीटर स्थापित करने के लिए एनर्जी एफिशिएंट सर्विस लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

» दिसंबर 2020 तक 2.15 लाख स्मार्ट मीटर लगाए गए।

» डिस्कॉम द्वारा स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट में प्रीपेड सुविधा, ट्रस्ट रीडिंग-बेस्ड बिलिंग, बिजली बिल ऑनलाइन देखने के लिए मिस्ड कॉल सुविधा, डाकघरों के माध्यम से बिजली बिल भरना, नए कनेक्शन के लिए उपभोक्ता संतुष्टि दर और डिलीवरी का औसत समय जैसी कई नागरिक-केंद्रित सेवाएं शुरू की गई हैं।

पिछले दो वर्षों में बिजली क्षेत्र में किये गए सुधारों के फलस्वरूप प्रदेश के चारों बिजली वितरण निगम मुनाफ़े में आ गये हैं। इसकी प्रशंसा केंद्र सरकार द्वारा की गई है और अन्य राज्यों को भी यह अनुसरण करने के लिए कहा गया है। राज्य में 'म्हारा गांव-जगमग गांव योजना' के माध्यम से 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने के भरसक प्रयास किए गए हैं और एक साल में सभी गांवों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी।

चौ. रणजीत सिंह, बिजली मंत्री, हरियाणा

बिजली सुधार

पिछले दो वर्षों में बिजली क्षेत्र में किये गए सुधारों के फलस्वरूप प्रदेश के चारों बिजली वितरण निगम मुनाफ़े में आ गये हैं। हरियाणा इस मामले में देश के समक्ष मॉडल बनकर उभरा है और अन्य राज्यों को इसकी अनुपालना करने को कहा है। यह पूरे हरियाणा के लिए गौरव की बात है। प्रदेश की इस उपलब्धि का श्रेय मुख्यमंत्री मनोहर लाल, बिजली विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को भी जाता है। इसी कड़ी में विभाग शीघ्र ही एक और अनूठी पहल करने जा रहे हैं, जिसमें विभाग के सभी श्रेणियों के कर्मचारियों से विभाग में और अधिक सुधार के लिये हर महीने लिखित सुझाव मांगे जाएंगे। इन सुझावों में से अच्छे सुझावों का वे स्वयं चयन करेंगे और ऐसे अधिकारियों व कर्मचारियों को, जिनके सुझाव बेहतर होंगे उन्हें पदोन्नत्ति सहित अन्य प्रकार से भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

लंबित नलकूप कनैक्शन होंगे जारी

कृषि नलकूप कनैक्शनों के लंबित बैकलॉग को पूरा करने के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार किया गया है, जिसके तहत हर सप्ताह डिविजन व सर्कलवार इनकी समीक्षा की जाएगी और आठ से दस विशेष टीमों को तुरंत दो से तीन हजार कनैक्शन जारी करने का कार्यक्रम सौंपा जाएगा। पहले 16 हजार लंबित कृषि नलकूप कनैक्शनों को जारी किया जाएगा और 30 जून, 2022 तक 40 हजार कनैक्शन जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पिछले वर्ष प्रदेश सरकार ने बिजली दरों में 37 पैसे प्रति यूनिट की कटौती की थी।

गलत बिजली बिलों को ठीक करने की कवायद

प्रायः यह देखने में आया है कि लगभग 16 प्रतिशत बिजली बिल विभिन्न कारणों से गलत जारी हो जाते हैं, चाहे वह मीटर में कमी की वजह से हो या घर बंद होने के कारण हो। इस त्रुटि को दूर करने के लिए हर ब्लॉक स्तर पर विशेष अभियान के तहत अधिकारियों की टीम भेजकर मौके पर इन बिलों को ठीक करवाया जाएगा। अगर बिजली बिल की राशि ज़्यादा है तो उपभोक्ता 25 प्रतिशत राशि जमा करवाकर शेष राशि की किश्तें बनवाकर इन बिलों को भर सकता है।

24 घंटे बिजली आपूर्ति

अब तक 5,427 गांवों को 'म्हारा गांव-जगमग गांव योजना' के माध्यम से 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है और आगामी एक वर्ष में प्रदेश के हर गांव में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जाएगी और ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन जाएगा। इसी प्रकार, मई और जून के महीनों में तेज़ आंधी के कारण बिजली के खम्भे गिर जाने से लाइन लॉसिस बढ़ जाते थे और इस समस्या से निपटने के लिए पोल मोफिंग तकनीक से खम्भे लगाएं जाएंगे, जिसमें ज़मीन में सीधे खम्भे न लगाकर उन्हें कंक्रीट और सीमेंट के साथ लगाया जाएगा।

आधारभूत संरचना सुधार प्राथमिकता

केंद्र सरकार ने राज्यों को बिजली आधारभूत संरचना सुधार के लिए फेज-1 के लिए 3 लाख करोड़ रुपए तथा फेज-2 के लिए 97 हजार करोड़ रुपए का विशेष पैकेज जारी किया है। फेज-1 में बिजली सब-स्टेशनों का सुधार किया जाएगा, जबकि फेज-2 में अन्य आधारभूत संरचना विकसित की जाएंगी। उनका प्रयास है कि बिजली विभाग में किये जा रहे सुधारों के साथ-साथ जेल विभाग में सुधार किये जाएं।

क्या कहना है उपभोक्ताओं का

फरीदाबाद के युवा सचिन मडोलिया का कहना है कि राज्य में अब बिजली की स्थिति पहले जैसी नहीं है और बिजली व्यवस्थाओं में काफ़ी सुधार आया है। गांवों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो रही है, जिससे उनके हर कार्य में आसानी हो रही है। यह राज्य सरकार के लिए काबिलेतारीफ़ है कि केंद्र सरकार द्वारा बिजली विभाग की सराहना की गई है और अन्य राज्यों को भी उनका अनुकरण करने के लिए कहा गया है।

रोहतक के नवीन का कहना है कि बिजली विभाग के कार्य काफ़ी हाईटेक हो गये हैं और ऑनलाइन बिजली बिल देखने के लिए मिस्ड कॉल सुविधा, स्मार्ट मीटर और डाकघरों से बिजली बिल भरने से उनकी काफ़ी समस्याएं हल हो गई हैं। अधिक बिजली मिलने से उन्हें ऑनलाइन काम करने में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता।

पलवल के किसान बोधराज रावत का कहना है कि राज्य सरकार के बिजली विभाग द्वारा किसानों को विशेष रियायतें दी जाती है, जिससे किसानों को बिजली बिलों का कम बोझ पड़ता है। कृषि नलकूप कनैक्शन से भी किसानों को लाभ मिल रहा है।

पलवल की ही गृहिणी अश्वनी का कहना है कि 24 घंटे बिजली मिलने से अब घरेलू काम आसानी से पूरे हो जाते हैं और उन्हें काम के लिए बिजली आने का इंतजार नहीं करना पड़ता। इसके साथ ही बच्चों को पढ़ाई पर कोई फ़र्क नहीं पढ़ रहा है और वह रात को अपनी पढ़ाई जारी कर सकते हैं।

भिवानी की वंदना सांगवान का कहना है कि अब हरियाणा में बिजली अच्छे ढंग से उपलब्ध हो रही है और उपभोक्ता भी समय पर बिजली के बिल भरते हैं। ऑनलाइन सुविधाओं ने भी उपभोक्ताओं के काम को बहुत आसान कर दिया है।

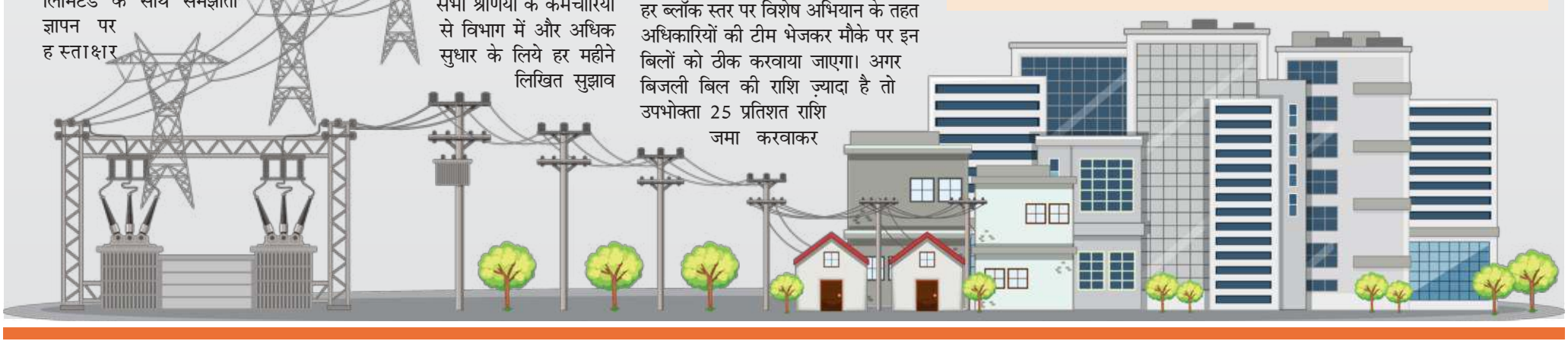

राज्य सरकार ने उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने 'हरियाणा माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजिज फैसिलीटेशन काउंसिल' सूक्ष्म और लघु उद्यमों की अपने खरीददारों से विलंबित भुगतान की वसूली की सुविधा के लिए गठित की है।

अंत्योदय सरल

सरकारी सेवाओं व योजनाओं के लाभ के लिए राज्य सरकार द्वारा 31 विभागों से संबंधित 546 सेवाओं को अधिसूचित किया गया है, जिनमें से 297 सेवाओं का लाभ अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से दिया जा रहा है।

हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर

श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत की इतिहास में कोई बराबरी नहीं है। वह एक महान विचारक, योद्धा, पथिक व आध्यात्मिक व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने धर्म, मातृभूमि और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया इसलिए उन्हें ''हिंद दी चादर'' का ताज पहनाया गया।

श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के महत्व को जानने के लिए सिख धर्म के इतिहास में उतरना होगा। श्री गुरु नानक देव जी ने उस समय सिख धर्म की स्थापना की जब समाज जाति आधारित अत्याचारों, बहिष्कार, भेदभाव, छुआछूत तथा धर्मान्तरण की चपेट में था। श्री गुरू तेग बहादुर ने श्री गुरू नानक देव जी व सभी गुरूओं के प्रकाश और दिव्यता को आगे बढ़ाते हुए गुरू परम्परा के अनुरूप ही धर्म व देश की रक्षा के लिए आवाज बुलन्द की।

देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने 17वीं शताब्दी में ही धर्म की आजादी के लिए शहादत देकर प्रत्येक देशवासी के दिलों-दिमाग में निडरता से आजाद जीवन जीने का बीज बो दिया था।

महान संत शिरोमणि, योद्धा व नौवें सिक्ख गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 21 अप्रैल 1621 में पंजाब के अमृतसर नगर में हुआ था। इन्होंने चकनानकी नामक स्थान को स्थापित किया, जिसका बाद में दसवें गुरु श्री गुरु गोबिंद जी ने आनंदपुर साहिब के नाम से विस्तार किया। श्री गुरु तेग बहादुर जी के बचपन का नाम त्यागमल था। मात्र 14 वर्ष की आयु में अपने पिता के साथ मुगलों के हमले के खिलाफ हुए युद्ध में उनकी वीरता से प्रभावित होकर उनके पिता ने उनका नाम त्यागमल से तेग बहादुर (तलवार के धनी) रख दिया। युद्धस्थल में भीषण रक्तपात से श्री गुरु तेग बहादुर जी के वैरागी मन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उनका मन आध्यात्मिक चिंतन की ओर हुआ। उन्होंने 20 वर्ष तक बाबा बकाला साहिब में साधना की।

तत्कालीन शासक औरंगजेब के दरबार में एक विद्वान पंडित हर रोज औरंगजेब को गीता श्लोक पढ़ता और उसका अर्थ सुनाता था, पर वह पंडित गीता में से कुछ श्लोक छोड़ दिया करता था। एक दिन पंडित बीमार पड़ गया और औरंगजेब को गीता सुनाने के लिए पंडित ने अपने बेटे को भेज दिया परन्तु उसे यह बताना भूल गया कि उसे किन-किन श्लोकों का अर्थ राजा के सामने नहीं करना है।

पंडित के बेटे ने जाकर औरंगजेब को पूरी गीता का अर्थ सुना दिया। औरंगजेब को किसी दूसरे धर्म की प्रशंसा व सच्ची शिक्षाएं सहन नहीं थी। औरंगजेब ने कश्मीर के गवर्नर इफ्तिकार खाँ को कहा कि सभी पंडितों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कहा जाए। गवर्नर ने कश्मीरी पंडितों को इस्लाम धर्म ग्रहण करने के लिए कहा, यदि वे ऐसा नहीं करते तो सभी को मौत के घाट उतारा जाएगा। इसके बाद सभी पंडित गुरु तेग बहादुर के पास गए और सारा वृत्तांत सुनाया।

गुरु तेग बहादुर जी ने पंडितों से कहा कि आप जाकर जालिम खां से कह दें कि यदि गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया तो उनके बाद हम भी ईस्लाम धर्म ग्रहण कर लेंगे और यदि आप गुरु तेगबहादुर जी से इस्लाम धारण नहीं करवा पाए तो हम इस्लाम धर्म धारण नहीं करेंगे। यह बात औरंगजेब तक पहुंची तो औरंगजेब 'ोधित हो गया और उसने गुरु तेग बहादुर को बंदी बनाने के लिए आदेश दे दिए।

1665 में गुरु तेग बहादुर व उनके तीन शिष्यों भाई मतिदास, भाई दयालदास तथा भाई सती दास को बंदी बनाया गया। जेल में भी काज़ी ने गुरु तेग बहादुर जी को प्रस्ताव दिया कि आप इस्लाम स्वीकार करके ही अपनी जान बचा सकते हैं, नहीं तो आपका

सिर कलम कर दिया जाएगा। उस समय ध्यानरत गुरु जी ने सिर हिलाकर इस्लाम स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

जब यह खबर औरंगजेब तक पहुंची तो वह आग बबूला हो गया। गुरु तेग बहादुर को डराकर इस्लाम स्वीकार करवाने के लिए उनके तीनों शिष्यों भाई मतिदास, भाई दयाल दास तथा भाई सती दास को उनकी आंखों के सामने अलग-अलग तरीके से मार दिया गया और कहा कि उनका भी यही हाल होने वाला है लेकिन गुरु तेग बहादुर अपने वचन से टस से मस नहीं हुए। उन्होंने श्रीमद्भागवत गीता के श्लोक -

श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठिता।
स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः।

से प्रेरणा लेकर धर्म की रक्षा के लिए कहा कि मैं सिक्ख हूँ और सिक्ख ही रहूंगा। इसके बाद 1675 में आततायी शासक औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर का शीश काट दिया। आज उसी स्थान पर गुरुद्वारा शीशगंज है, जो हिन्द-सिक्ख भाईचारे का जीता-जागता प्रमाण है।

शीश काटने के बाद उनका सिर भाई जैता अपने घर ले आए। तब भाई जैता की पत्नी ने गुरु जी का शीश उनके बेटे गोबिन्द राय को सौंपने के लिए कहा। भाई जैता ने श्री कीरतपुर साहिब जी पहुंचकर गोबिन्द राय को श्री गुरू तेग बहादुर साहिब जी का शीश समर्पित किया। इसके बाद आनन्दपुर साहिब में दाह संस्कार किया गया।

संसार को ऐसे बलिदानियों से प्रेरणा मिलती है, जिन्होंने जान दे दी परंतु सत्य-अहिंसा का मार्ग नहीं छोड़ा। नवम पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के बाद उनके सुपुत्र श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी दशम पातशाही के गुरु साहिब बने, जो एक महान योद्धा, कवि तथा दार्शनिक थे।

गुरु तेग बहादुर जी ने कहा था कि धर्म एक मजहब नहीं, धर्म एक कर्तव्य है। आदर्श जीवन का रास्ता है। आज हमारे लिए गुरू जी की शिक्षाएं, त्याग, बलिदान एक धरोहर हैं। इस धरोहर को बचाने व सहज कर रखना ही गुरू जी के प्रति सच्ची श्रद्धा होगी।

-श्री बंडारू दत्तात्रेय, राज्यपाल

एक गुमनाम लेखक

जिसने 6 महीनों में 251 पन्नों का संविधान हाथ से लिखा

भारतीय संविधान-दुनिया के किसी प्रभुत्व-सम्पन्न देश का सबसे लंबा लिखा गया संविधान है । ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष डॉ. आंबेडकर को भारतीय संविधान का रचियता होने का श्रेय प्राप्त है। लेकिन, बहुत कम लोग उस शख्स के बारे में जानते हैं, जिन्होंने खुद अपने हाथों से पूरे संविधान को लिखा!

26 नवंबर 1949 को संविधान का पहला ड्राफ्ट बनकर तैयार हुआ और ये किसी उत्कृष्ट कृति से कम नहीं है। हमारे संविधान के हर एक पेज के बॉर्डर को नन्दलाल बोस और उनके छात्रों ने डिज़ाइन किया और इसे खूबसूरत कलाकृतियों से सजाया।

लेकिन संविधान के प्रस्तावना और अन्य विषय-वस्तुओं को ज़िन्दगी दी, प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा ने। 17 दिसंबर 1901 को कैलिग्राफर्स/ सुलेखकों के घर में जन्में प्रेम बिहारी ने बहुत ही कम उम्र में अपने माता-पिता को खो दिया। उनका लालन-पोषण उनके दादाजी मास्टर राम प्रसादजी सक्सेना और चाचा, महाशय चतुर बिहारी नारायण सक्सेना ने किया। उनके दादाजी पारसी और अंग्रेजी भाषा के स्कॉलर थे। यहाँ तक कि उन्होंने

अंग्रेजों को भी पारसी भाषा पढ़ाई थी।

प्रेम बिहारी ने कैलीग्राफी अपने दादाजी से सीखी। दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से ग्रेजुएशन पास करने के बाद प्रेम बिहारी कैलीग्राफिक आर्ट में मास्टर हो गए थे। इसलिए जब भारतीय संविधान बनकर प्रिंट होने के लिए तैयार था तो जवाहरलाल नेहरू ने उनसे इसे फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल में हाथ से लिखने की गुजारिश की। नेहरू ने उनसे पूछा कि इस काम की वह कितनी फीस लेंगे। इस पर उन्होंने कहा-एक पैसा भी नहीं। मेरे पास भगवान की दया से सब कुछ है और मैं अपनी ज़िन्दगी में खुश हूँ, पर मेरी एक शर्त है कि इसके हर एक पन्ने पर मैं अपना नाम और आखिरी पन्ने पर अपना और दादाजी का नाम लिखूंगा।

उनकी इस शर्त को मानकर, भारत सरकार ने प्रेम बिहारी को भारतीय संविधान अपने

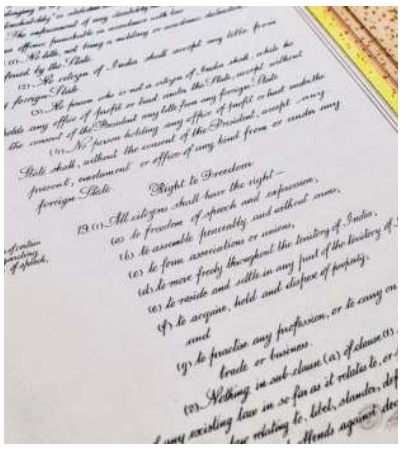

हाथों से लिखने का अनमोल काम सौंपा। उन्हें संविधान हॉल (बाद में संविधान क्लब हो गया) में एक कमरा दिया गया। उस समय संविधान में, कुल 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल, और एक प्रस्तावना थी। प्रेम बिहारी को यह काम पूरा करने में 6 महीने लगे। इस पूरी प्रक्रिया में 432 पेन-होल्डर निब्स का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कैलीग्राफी के लिए 303 नंबर की निब का इस्तेमाल किया। निब को लकड़ी के होल्डर में लगाकर और फिर उसे स्याही में डुबोकर लिखने के लिए इस्तेमाल किया गया। संविधान की वास्तविक पांडुलिपि 16 गुणा 22 इंच की पार्चमेंट कागज़ पर लिखी गयी, जिसका जीवनकाल लगभग 1000 वर्ष का होता है। संविधान की पांडुलिपि में 251 पन्ने हैं, जिसका वजन 3.75 किग्रा है। देहरादून में स्थित सर्वे ऑफ इंडिया के कार्यालय में संविधान की हस्ताक्षरित पांडुलिपि को फोटोलिथोग्राफिक तकनीक से प्रकाशित किया गया था। हालांकि, हैरानी की बात यह है कि संविधान की प्रस्तावना की तरह, इसके पन्नों को मूल डिज़ाइन और लेखन के साथ वितरित नहीं किया गया।

-सुरेंद्र बांसल

सोलर पम्प पर भारत सरकार की ओर से 35 प्रतिशत तथा हरियाणा सरकार की ओर से 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। किसान को केवल कुल लागत का 25 प्रतिशत खर्च ही वहन करना पड़ता है।

कोविड के कारण हुई मृत्यु के मामलों में मृतक के निकटतम संबंधी को 50,000 रुपए प्रति केस के अनुसार अनुग्रह सहायता प्रदान करने के लिए अंत्योदय सरल पोर्टल पर ऑनलाइन सेवा शुरु की गई है।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में हरियाणा की धूम

हरियाणा सरकार की नीतियों व जनकल्याणकारी योजनाओं की तारीफ़ न केवल स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी की गई है बल्कि उनका अन्य राज्यों में भी अनुकरण किया जा रहा है। सुशासन व अच्छे कार्यों के लिए हरियाणा सरकार सभी के सुझावों का सदैव स्वागत करती है। हरियाणा सरकार प्रधानमंत्री के दिखलाए मार्ग 'सबका साथ-सबका विकास, सबका विश्वास- सबका प्रयास' पर अग्रसर है।

मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा

हरियाणा देश के सर्वाधिक प्रगतिशील राज्यों में शामिल है। प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में हुई उन्नति को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 14 नवंबर से 27 नवंबर तक आयोजित 40वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला में प्रदर्शित किया गया। एक आदर्श निवेश गंतव्य-अंतहीन अवसर के संदेश के साथ हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम के विभिन्न मेगा फूड पार्क , फुटवियर पार्क, आईएमटी व अन्य औद्योगिक क्षेत्रों का विवरण प्रदर्शित किया गया। इस वर्ष भी 'आत्मनिर्भर भारत-आत्मनिर्भर हरियाणा' विषयवस्तु के साथ 'हरियाणा मंडप' आकर्षण का केंद्र रहा। मंडप में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विजन और राज्य सरकार द्वारा शुरु की गई नई पहलों को प्रदर्शित किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा राज्य दिवस के अवसर पर भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला में हरियाणा मंडप का अवलोकन किया। इस दौरान सांस्कृतिक संध्या में कलाकारों ने शानदार हरियाणवी सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दीं ।

प्रगति की चर्चा करें तो हरियाणा का वर्ष 1967-68 में 4.5 करोड़ रुपए का निर्यात बढ़कर वर्ष 2020-21 में 1,74,572 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इनके अलावा हरियाणा कृषि एवं व्यवसाय नीति, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग नीति तथा हरियाणा उद्यम एवं रोज़गार नीति, एक खंड-एक उत्पाद, एकीकृत विमानन हब, कौशल विकास प्रशिक्षण के मिशन के रूप में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का विवरण प्रदर्शित किया गया।

तकनीकी शिक्षा के विकास और तकनीकी विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेजों, बहुतकनीकी संस्थानों व अन्य संस्थानों का विवरण दिया गया। इसके अतिरिक्त आईआईआईटी सोनीपत, आईआईएम रोहतक, नेशनल इंस्टीट्यूट आफ डिजाइन कुरुक्षेत्र व नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फैशन टेक्नोलॉजी का विवरण दिया गया। मंडप में सजी खेल नीति आकर्षण का केंद्र रही।

5,367 गांवों में 24 घंटे बिजली

विद्युत क्षेत्र में हरियाणा के विद्युत निगमों का लाभ में होने तथा 'म्हारा गांव जगमग गांव' योजना के परिणामस्वरूप हरियाणा के दस जिलों में चौबीस घंटे विद्युत आपूर्ति की दर्शाया गया। हरियाणा के 5,367 गांवों में 24 घंटे व 1,658 गांवों में 16 घंटे से 18 घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है, जो औद्योगिकरण को खुला निमंत्रण है।

-संवाद ब्यूरो

तू सामने आता है तो तेरा सजदा कर लेता हूं....

आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रमों की श्रृंखला में हरियाणा के सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा टैगोर थियेटर में 'सजदा' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की गरिमामयी उपस्थिति रही।

हरियाणा सरकार में मुख्य सचिव, जो गायकी और शायरी के फनकार हैं, विजय वर्धन ने ''नमाज आती है मुझे न वजू आता है, तू सामने आता है तो तेरा सजदा कर लेता हूँ.... '' शेर प्रस्तुत किया तो पूरा थियेटर करतल ध्वनि से गुंजायमान हो गया।

'सजदा' कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन की एक के बाद एक लाज़वाब प्रस्तुति ने दर्शकों को भाव-विभोर कर दिया। वाद्ययंत्रों की झंकार के बीच बही सुरीली रसधार में श्रोता करीब दो घंटे तक डुबकी लगाते रहे। पदमजीत सहरावत के गीतों की जुगलबंदी ने खूब वाह-वाही बटोरी।

आजादी के अमृत महोत्सव को देखते हुए मौके की नजाकत के अनुसार श्री विजय वर्धन ने मशहूर शायर फ़ैज के शेर -''बोल के लब आजाद हैं तेरे...'' ने श्रोताओं में देशभक्ति के नए जोश का संचार कर दिया। उन्होंने अंग्रेजी शासनकाल द्वारा हिंदुस्तानियों पर किए गए जुल्म-ओ-सितम का विभिन्न शेर-ओ-शायरी के माध्यम से ऐसा वर्णन किया कि हॉल में मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए।

सुण छबीले बोल रसीले

इलाज में मददगार 'स्वस्थ हरियाणा'

छबीले ने खेत में जाने के लिए अपनी पुरानी बाइक उठाई। थोड़ी दूर गली में चला था तो रसीले के घर के बाहर रुक गई। कई बार किक लगाई लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। देखा तेल कम है। तेल को रिजर्व लगाने वाली नोब टूटी हुई थी, उसे घुमाने के लिए प्लास की ज़रूरत पड़ गई।

छबीले ने रुक्का दिया- अरै रसीले, प्लास लेर्‌या सै के?

रसीला बोल्या- प्लास तो कोनी छबीले, माचिस लेर्‌या सूं। एक ना आधी, दो-दो।

छबीले ने कहा, उसनै के मैं सिर में मारुंगा?

- आग ला दिए।

-भूंडा बोलै, शरमा ले। भाभी नै बताद्यूंगा।

-बता दे मैं के डरूं सूं।

-मनैं तेरे तैं कितणी बार कह ली, यो बाइक पुराणी हो ली, नई ले ले।

-बात पुरानी, नई की कोन्या, कई दिन पाछै काढ़ी सै। ज्यांए तै अळबाद कर री सै।

-इसनै आड़ीए छोड़ दे, ले चाबी, म्हारी आली बाइक ले ज्या। पर तूं खेत में के करण जा सै?

-भाई आज पाणी का ओसरा सै। गेहूं की पळे करण जा सूं।

-छबीले थारी तो मौज होगी। ना तो कड़ै थारे खेतां में नहर का पाणी आया करता।

-भाई रसीले इस सरकार में जाकै खेतां नै नहर का पाणी दिख्या सै। वरना सारी उम्र बीतगी ट्यूबवैल के खारे पाणी तैं काम चलाते। अरै म्हारी बात छोड, उड़ै नारनौल कान्या म्हारे रिश्तेदारां के खेत कतई टिब्यां में सैं। नहर की टेल तैं भी कई किल्लां आगै। कदे टेल ताहीं पाणी कोन्या आया था। खट्टर सरकार नै टेल तैं आगै रिश्तेदारां के खेतां ताहीं भी नहर का पाणी पहुंचा दिया।

-पर रसीले तूं क्यूकर कांबल की बुक्कल मारे बैठा सै? किमे घणाए जाड्डा लागर्‌या सै।

- हां छबीले, मनै तो बेरा ना जाड्डा घणा लागैए सै।

-भाई, देही में जान कम सै, ऐकले गूंद तैं कोन्या काम चालै। बथूवे और सरसम का हरा साग, गाजर, मूली, शलगम खाया कर, इन दिनां में गुड़ बहुत बढ़िया बताया। बहुत से लोग जाड्डां में पानी कम पीवैं सैं। यो बहुत बड़ी गलती करैं सैं। पाणी जरुर पीया करो। जड़े ताहीं हो सकै हल्का गर्म पाणी पीयो। तड़कै खाली पेट जरुर नुआया पाणी पीणा चाहिए। बीमारियां तैं बचे रहंगे। दखे लापरवाही करी या

बाजार की चाट-पत्ती में रहे तो बीमार होज याओगे। डाक्टर कै जाणा होगा तो घणे रपइयां में पांडा छूटैगा।

-भाई, प्राइवेट डाक्टर तो महंगा पड़ै सै। सरकारी में जाणा चाहिए। ईब तो सरकार नै 'स्वस्थ हरियाणा' के नाम तैं एक ऐप मोबाइल फोन मं दी सै। घरां बैठे उस ऐप में आपणे नाम का रजिस्ट्रेशन करा दें। एक तरियां पर्ची घरां बैठे बणज्या सै। अस्पताल में आराम तैं जाओ और बिना लाइन में लागे डाक्टर धौरै जाकै आपणा इलाज कराओ। इतणा ऐ नहीं इस ऐप पै टेस्टां की रिपोर्ट और टीकाकरण की जानकारी भी मिलज्यागी। इलाज कराणे के बाद फेर कदे अस्पताल में जाणा हो तो योए रिपोर्ट ऐप में फेर मिलज्यागी, जिसनै देखकै डाक्टर फेर इलाज कर देगा। अस्पताल में दवाइयां की कोए कमी कोन्या। सरकार की ओर तैं जमा फ्री में दवाई मिलज्या सैं।

-हां भाई रसीले, अस्पतालां पे सरकार खर्चा बहुत करै सै। रोज करोड़ां रुपए खर्च हो सैं। पर माणस भी चाळै के सैं। माड़ी सी हरकत होते ही शहरां कान्या भाज ले सैं। न्यू नहीं अक गाम की डिस्पेंसरियां में चले जां। पहली बात तो घर में और आसपास में साफ सफाई राखैं, खाणे पीणे पै ध्यान दें। फेर भी कोई तकलीफ होज्या तो अस्पताल में जां। और भाई जिसका नरम ब्यौंत सै और बड्डी सी बीमारी होज्या, तो सरकार ने 'आयुष्मान योजना' चला राखी सै। जिसमें सरकार की तरफ तैं फ्री में इलाज हो सै।

-छबीले, सरकार नै काम तो खूब करे सैं और करण लागरी सै। ईब तो सरकार रोज़ बुक्कल में बैठे-बैठे देसी घी का एक-एक कटोरा हलुआ भी दे दे तो ठीक होज्या।

- वाह रसीले, तूं हाथ पां ना हिलाइये, सबकुछ सरकार ए कर देगी। ल्या बाइक की चाबी दे, अलकसी आदमी।

-मनोज प्रभाकर

डॉ अमित अग्रवाल, भा.प्र.से. प्रबंध निदेशक, संवाद (सूचना जन संपर्क एवं भाषा विभाग) हरियाणा द्वारा हरियाणा सरकार के लिए कमरा नं. 314, दूसरी मंजिल, लघु सचिवालय, सेक्टर-1, पंचकूला से प्रकाशित।
कार्यालय : संवाद सोसायटी एससीओ 23, पहली मंजिल, सेक्टर 7, चंडीगढ़ फोन : 0172-2723814, 2723812 email : editorsamvad@gmail.com